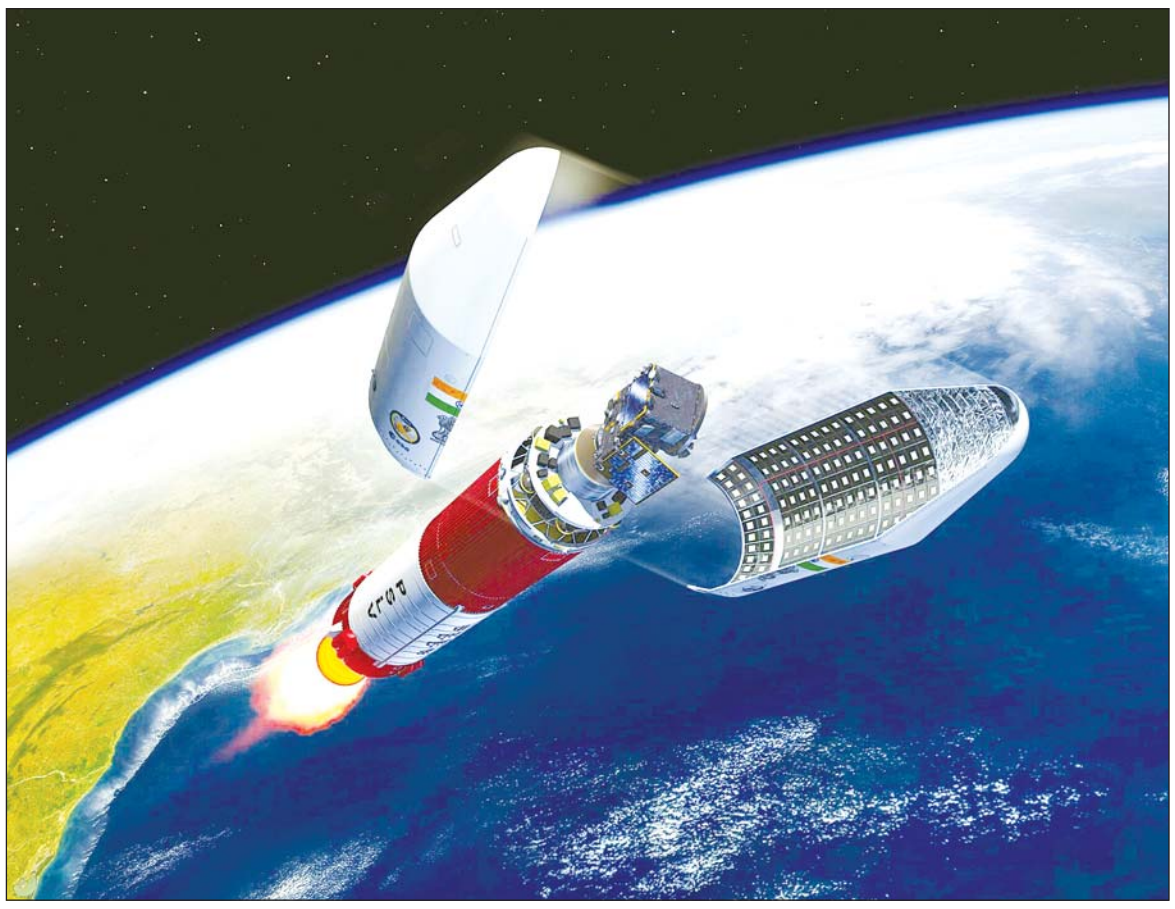

इसरो ने फिर कीर्तिमान रचा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। प्रोबा-3 मिशन के जरिए वैज्ञानिक सूर्य के अंदरूनी और बाहरी कोरोना के बीच बने काले घेरे का अध्ययन करेंगे। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के ऑस्ट्रेलिया स्थित उपग्रह स्टेशन ने प्रोबा-3 का भेजा पहला संदेश प्राप्त किया। ईएसए के महानिदेशक जोसेफ एशबैकर ने कहा कि यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण को 'शानदार बढ़ावा' देगा। इसे अंतरिक्ष में शानदार ढंग से स्थापित करने के लिए इसरो का धन्यवाद।

सी.एम. ने ''कर्मभूमि से मातृभूमि'' पर जल शक्ति मंत्री से चर्चा की

मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादव भी चर्चा में शामिल थे

नई दिल्ली/जयपुर, 5 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात कर ''कर्मभूमि से मातृभूमि'' अभियान पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद थे।

■ **इस कार्यक्रम में प्रवासी नागरिक मातृभूमि के विकास में योगदान देते हैं। राजस्थान में इस कार्यक्रम में भूजल के स्तर में बढ़ोतरी के लिये 45 हजार ट्यूबवैल रीचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण होगा।**

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संचय के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ''कर्मभूमि से मातृभूमि'' कार्यक्रम की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत प्रवासी बंधुओं की जनभागीदारी के माध्यम से मातृभूमि के विकास में योगदान के रूप में राजस्थान राज्य में भूजल स्तर में बढ़ोतरी के लिए 45 हजार ट्यूबवैल रीचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। यह अभियान प्रदेश में वॉटर रीचार्ज के क्षेत्र में वरदान साबित होगा।

उल्लेखनीय है कि इस अभियान के अंतर्गत राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं बिहार के प्रवासी बंधुओं द्वारा भूजल पुनर्भरण हेतु आधुनिक रीचार्ज शाफ्ट्स का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में युवाओं के रोजगार व कौशल विकास के लिए किए जा रहे कार्यों एवं अन्य जनकल्याणकारी विषयों पर सार्थक चर्चा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस के मुंबई में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री फडनवीस तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे व अजित पवार को बधाई दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, अनेक केन्द्रीय मंत्री तथा कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे।

'बगैर ट्रैक्टर-ट्रॉली वाले किसान को रोकना अलोकतांत्रिक'

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा सरकार की बात मानकर किसान बिना ट्रैक्टर-ट्रॉली दिल्ली जाना चाहते थे

चंडीगढ़, 05 दिसंबर (वार्ता)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कहा कि किसानों ने सरकार की बात मानते हुये बिना ट्रैक्टर-ट्राली के दिल्ली जाने की बात मान ली है, ऐसे में उनको रोकना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। हुड्डा ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सभी को प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी आने-जाने या अपनी बात कहने का अधिकार है।

■ **उन्होंने यहा पिछली बार आंदोलन खत्म करवाते समय सरकार ने एमएसपी के लिये कमेटी बनाने का ऐलान किया था। लम्बा समय बीत जाने पर भी कुछ नहीं हुआ।**

उन्होंने कहा कि पिछली बार आंदोलन खत्म करवाते हुये सरकार ने न्यूनतम समर्थ मूल्य (एम.एस.पी.) के लिये बाकायदा एक कमेटी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसानों के हाथ खाली हैं और वे सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा किसानों को बिजाई के समय डी.ए.पी., सिंचाई के समय यूरिया और कटाई के समय एम.एस.पी. देने में हमेशा नाकाम साबित हुई है। यही वजह है कि बार-बार अपनी मांगों को लेकर किसानों को आंदोलन करना पडता है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार विज्ञापनों में 24 फसलों पर एम.एस.पी. देने की बात कहती है, जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा में कुल 24 फसलें होती ही नहीं हैं और जो फसलें होती हैं, उन पर भी किसानों को कभी एमएसपी नहीं मिलती। धान का उदाहरण सभी के सामने है। चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने किसानों को 3100 रु धान का दाम देने का ऐलान किया था लेकिन चुनाव के बाद सरकार अपने वादे को भूल गई और किसानों को एम.एस.पी. तक नहीं मिल पाई।

कांग्रेस नेता ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने को भी आलोकतंत्रिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसकी बात को सुना जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण प्रतिबंधों पर सशर्त ढील दी

नयी दिल्ली, 05 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गंभीर स्तर के वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों में कुछ शर्तों के साथ ढील देने की गुरुवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की गुहार पर ग्रेडेड रैस्पॉंस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-4 से 2 तक नीचे जाने की अनुमति दी। न्यायालय ने हालांकि सी.ए.क्यू.एम से कहा कि उसे चरण 3 से कुछ अतिरिक्त अतिरिक्त उपाय लागू करने होंगे।

गैर आर.ए.एस. से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पदोन्नति के लिये अधिक से अधिक 15 प्रतिशत सीटों को एक कोटा ही माना जायेगा, को वर्तमान में भी ना जाने क्यों जारी रखा गया है? इस संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की ओर से पिछली सरकार के मुख्य सचिव की एक ''नोट शीट'' को भी पेश किया।

तनवीर अहमद और आर.एन.माथुर का कहना था कि इस नोट शीट में सीटों का मूल्यांकन गलत तरीके से किया गया और स्पष्ट रुप से कहा गया कि गैर आर.ए.एस. अफसरों की आई.ए.एस. पदों के लिये चार सीटें रिक्त हैं। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि 17 फरवरी 2023 को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए पत्राचार से भी स्पष्ट होता है कि दोनों ने वर्ष 2022 के लिये गैर आर.ए.एस. अफसरों के लिये चार सीटों का ''कोटा'' तय किया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि हर वर्ष की पदोन्नति की रिक्तियां उसी वर्ष में समाप्त हो जाती है और यह अगले वर्ष की रिक्तियों में नहीं जोड़ी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की चयन समिति हर वर्ष बैठकर तय करती है कि उस वर्ष कितनी पदोन्नति होंगी। सरकार पिछले वर्ष की रिक्तियों को इस वर्ष नहीं जोड़ सकतीं, ऐसा करना नियमों के विरूद्ध जाकर ''कोटा'' तय करने के समान होगा।

उन्होंने अदालत को कहा कि नियम में 15 प्रतिशत रिक्त पद गैर आर.ए.एस. से भरे जाने के लिये ''विशेष परिस्थितियों'' का वर्णन है, जिनमें ''आउटस्टेंडिंग'' श्रेणी के उम्मीदवारों की भरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा कि इस वर्ष ऐसी क्या विशेष या विकट स्थिति थी कि उन्हें 15 प्रतिशत सीटें इन अभ्यर्थियों से भरनी पड़ी, और यह कह देना कि, पिछली सरकार में भी यह किया गया था, पर्याप्त नहीं है।

इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि सरकार नियमानुसार आई.ए.एस. के कुछ फीसदी पद गैर आर.ए.एस. से भर सकती है। दूसरी सेवाओं से अधिकारी को पदोन्नति देने से पूर्व उनकी विशेषज्ञता की जांच की जाती है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आई.ए.एस. प्रमोशन नियम, 1954 के तहत इस तरह से प्रमोशन करती आ रही है। इसके अलावा याचिका में दूसरी सेवाओं से आने वाले कार्मिकों की योग्यता को चुनौती नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन चाहती है कि सिर्फ उनके संगठन के सदस्य ही आई.ए.एस. पदों पर पदोन्नत हो। उन्होंने अदालत को कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका की आड़ में पदोन्नति के नियमों को चुनौती देना चाहते हैं, जिनमें तीनों श्रेणियों के नियम हैं।

सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील तनवीर अहमद ने कहा कि वे अपने मुवक्किल से बात करके उन्हें सलाह देंगे कि वह इस आदेश को एस.एल.पी. के माध्यम से चुनौती दें।

अमेरिका ''क्रिसमस ट्री'' के आयात...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भगवान की मूर्तियां और सजावट के बिजली के बल्बों की लड़ियां शामिल हैं। भारत चीन से 96 अरब डॉलर का आयात करता है और इसके एवज में चीन हमारी सीमा में घुसपैठ करता है हमारी जमीन हड़पता है।

भारत चीन से आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। भारत का दवा उद्योग चीन से ही कच्चा माल आयात करता है जिससे दवा बनती है यही नहीं चिकित्सकीय उपकरण भी चीन से आते हैं। दूसरी ओर अमेरिका चीन से एक खरब डॉलर का आयात करता है और नव निर्वाचित राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं कि चीन के माल पर भारी शुल्क लगाएंगे। चीन व अमेरिका के बीच जबरदस्त ट्रेड वॉर लड़ा जाएगा।

इसके अलावा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने यह भी कहा, ब्रिक्स देशों में अगर अमेरिकन डॉलर के इस्तेमाल में कमी करने की कोशिश की तो उन पर 100 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा उन्होंने कड़े शब्दों में धमकी दी है।

ब्राजील में आयोजित पिछले ब्रिक्स सम्मेलन में, सहभागी देशों ने डॉलर वैकल्पिक मोड्स के उपयोग के विचार में ऊपरी तौर पर दिलचस्पी दिखाई थी किन्तु व्यापार-सन्तुलन के सैटलमेन्ट्स के लिये ही अमेरिकन डॉलर पर निर्भरता हो।

इसके बाद, डॉलर के उपयोग की स्थिति स्पष्ट करना और जरूरी हो गई, क्योंकि यूक्रेन-युद्ध शुरू हो जाने के बाद अमेरिका ने रूस पर विभिन्न प्रतिबन्ध लगा दिये थे। रूस पर सीधे ही प्रतिबन्ध लगाने के तुरन्त बाद ही, अमेरिका ने उन देशों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये थे, जो रूस या ईरान के साथ व्यापार या सौदे कर रहे थे।

इसी संदर्भ में, अमेरिका ने अपना दबदबा दिखाते हुये, रूसी बैंकों को प्रभावशाली इन्टरनेशनल बैंक्स सैटलमेन्ट्स मैकेनिज्म, अर्थात एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. नैटवर्क से बाहर कर दिया था। अमेरिका ने कह दिया था कि प्रतिबन्धित देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले अन्य देशों के बैंक भी ''स्विफ्ट'' नैटवर्क से बाहर कर दिये जायेंगे।

रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका की धमकियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा था कि अमेरिका जिस तरह से अपनी मुद्रा का उपयोग कर रहा है उसके चलते डॉलर के विकल्प निश्चित रूप से उभर कर आयेंगे। अमेरिका जिस तरह से डॉलर को काम में ले रहा था, उस तरीके की रूस के राष्ट्रपति ने निन्दा की थी।

पुलिस ने कहा कि रूस डॉलर से दूर नहीं हो रहा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस को डॉलर के प्रयोग से अमेरिका ही रोक रहा है, रूस नहीं।

लेकिन इस बात पर विश्वास करना अकारण नहीं है कि ट्रेड वॉर जोरों पर है तथा डॉनल्ड ट्रम्प इसे घोर टकराव के स्तर तक ले जा रहे हैं।

'मर्यादाओं को ताक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वेणुगोपाल ने कहा कि शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशिकांत दूबे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वायनाड से सांसद श्रीमती वाड्रा के साथ-साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

प्रियंका ने कहा,देश की जनता चाहती है कि अडानी महा घोटाले पर संसद में चर्चा हो। इंडिया समूह के सभी दल संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं लेकिन नरेन्द्र मोदी और सरकार लगातार चर्चा से भाग रहे हैं। सारी मर्यादाओं को तार-तार करते हुए प्रधानमंत्री जिस तरह अडानी के भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं, वह बेहद हैरान करने वाला है। आज साथी सांसदों के साथ इस मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

टैटू के कारण अयोग्य...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ता के लिए खाली रखने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अंतरिम आदेश से याचिकाकर्ता के कोई हित सृजित नहीं होंगे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश दिलखुश बैरवा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता एस.के. सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन आयोग ने 24 नवंबर, 2023 को केन्द्रीय पुलिस बल में कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने एस.सी. वर्ग में भाग लिया और सफल हुआ। उसका बीकानेर में 29 अक्टूबर, 2024 को दस्तावेज सत्यापन भी हो गया। याचिका में कहा गया कि उसे यह कहते हुए अनफिट घोषित कर दिया कि विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण में उसके हाथ की कलाई पर उसके नाम का टैटू (गोदना) बना हुआ है।

इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि सामाजिक प्रथा के चलते, बचपन में उसके दाएं हाथ पर यह टैटू बनाया गया था और अब सर्जरी के जरिए उसे हटा दिया गया है। ऐसे में उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। यदि अंतिम भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित हो जाएंगे।

मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करते हुए एक पद रिक्त रखने को कहा है।

'समझौते'' के बाद दोनों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निन्दा करते हैं।'' असल में कांग्रेसी सांसद सदन में ''मोदी-अडानी एक है'' नारा लिखी टी शर्ट पहनकर आए थे।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने सदन में कहा कि यहाँ संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है। कई सदस्यों ने एक्ट का नाम हिन्दी में होने पर चिन्ता जाहिर की। इस पर उन्होंने कहा, ''मुझे तेलुगूभाषी होने पर गर्व है। मैं तेलुगू लिखता और बोलता हूँ.. लेकिन ''वायु'' तथा ''भारत'' जैसे शब्द तो तेलुगू में भी इसी रूप में हैं। विधेयक के टैक्स्ट अंग्रेजी में है, इसलिये किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये।'' राज्य सभा में ''भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा हो गई।

द्रमुक सांसद कनिमोई एन.वी.एन. सोमू ने भी कहा कि केन्द्र विधेयकों के नाम केवल हिन्दी और संस्कृत में रखने से बाज आये। उन्होंने सरकार से यह भी कहा कि वह इस विधेयक का नाम बदलकर ''एयरक्राफ्ट बिल 2024'' कर दे। माकपा सांसद ए.ए. रहीम ने कहा कि केन्द्र सरकार का ''भारतीय उड्डयन क्षेत्र तीन लोगों के ग्रुप के नियन्त्रण में है- टाटा, इंडिगो तथा अडानी।''

उन्होंने आगे कहा कि सभी बड़े हवाई अड्डे अडानी के नियन्त्रण में है तथा उड़ानों पर टाटा और इंडिगो का अधिपत्य है। अन्य सांसदों की तरह, रहीम ने भी हवाई जहाजों का किराया हद से ज्यादा होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, ''प्राइवेट कम्पनियाँ किराया तय कर रही हैं।''

आई.यू.एम.एल. सांसद हरीश बीरन ने कहा कि पुराने एक्ट में आर्थिक नियमन का प्रावधान था, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है।.. नया संशोधन ''नई बोतल में पुरानी शराब ही है। वीरन ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों में जिम्मेदारी दी गई है लेकिन हवाई किराये के लिये सीमा निर्धारित करने वाला कोई नियामक तन्त्र नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि छुट्टियों के मौसम में हवाई किराये बढ़ जाते हैं, तथा एक्ट में इसे रोकने की व्यवस्था होनी चाहिये।

बीजू जनता दल सांसद सुलातो देव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वो वादे याद दिलाये कि हवाई यात्रा ''उड़ान'' जैसी स्कीमों के जरिये आम आदमी की पहुँच में की जायेगी लेकिन साफ जाहिर है कि इस दिशा में कुछ खास काम नहीं किया गया है। आँकड़ों के अभाव का जिक्र करते हुये, उन्होंने कहा, ''ऐसी स्कीमों के तहत कितने लोगों को लाभ मिला है?'' इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद में अडानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के अन्तर्गत ''मोदी अडानी एक है'' लिखी हुई जैकेट पहनी हुई थीं।

राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुये, संसदीय जाँच की माँग की। टी.एम.सी. इस प्रदर्शन से दूर रही।

तृणमूल सांसद सागारिका घोष ने कहा, ''इंडियन पेनल कोड'' का नाम बदलकर ''भारतीय न्याय संहिता'' कर दिया गया है। ''द इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट'' का नाम ''द भारतीय वायुयान विधेयक'' कर दिया गया है। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, जो नया हो। सरकार स्वयं को ''गेम चेन्जर'' सरकार के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हैं, लेकिन यह केवल ''नेम चेन्जर'' सरकार है।

उन्होंने कहा, ''बहुत सारे अधिनियमों के हिन्दी नाम क्यों हैं। यह हिन्दी को थोपना है। 2024 में जनता का जनादेश विविधता तथा संघ सिद्धान्त के पक्ष में था। सरकार अधिनियमों के ''हिन्दीकरण'' पर तुली हुई है। यह हिन्दी को थोपना है। संविधान का अनुच्छेद 348 कहता है कि संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अंग्रेजी भाषा में होगा।''

'अडानी ग्रुप...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खिलाड़ी और थे-एजर पावर इंडिया लि. तथा नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड।

नवयुग इंजीनियरिंग, अडानी समूह के साथ आंध्रप्रदेश में अपने बंदरगाह को बेचने के लिए हज़ारों करोड़ रूपए के सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद नीलामी से बाहर हो गई, जिसके लिए पहले से बातचीत चल रही थी और साथ-साथ दोनों ही सौर ऊर्जा अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा भी कर रहे थे।

अब, एजर पावर पर आरोप है कि उसने अडानी समूह के साथ मिलीभगत करके राज्य सरकार के अधिकारियों को 2 हज़ार करोड़ रूपए की रिश्वत दी, एस.ई.सी.आई. के माध्यम से उनसे महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए।

डैंटल ऑफिसर भर्ती...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मांगी गईं। इस पर याचिकाकर्ताओं ने चार प्रश्नों के विवादित उत्तरों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। इसके बावजूद आपत्तियों का निस्तारण कर भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि उनके चार प्रश्नों के उत्तर सही थे, लेकिन उनके उत्तरों को गलत माना है। जबकि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंत शिक्षा परिषद से अनुमोदित पुस्तकों में बताए जवाब ही लिखे हैं। वहीं, आर.यू.एच.एस. ने जो किताब पेश की है वह न तो दंत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है और ना ही प्रदेश में चलती है।

आर.यू.एच.एस. के अधिवक्ता रामसिंह भाटी ने अदालत को बताया कि मान्यता प्राप्त पुस्तकों और विशेषज्ञ कमेटी की ओर से प्रश्नों का परीक्षण करने के बाद ही उत्तर कुंजी जारी की गई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

'राहुल गांधी अव्वल नम्बर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा हमेशा इनकी कड़ी आलोचना करती रहती है, पर राहुल पर हमला करने के लिए फ्रांस के प्रकाशन ''मीडिया पार्ट'' की एक रिपोर्ट का सहारा लिया और दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खोजी पत्रकारिता की बड़ी मीडिया कम्पनी ऑर्गनाइज्ड क्राइम एण्ड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजैक्ट (ओ.सी.सी.आर.पी.) तथा अमेरिका से गुप्त सम्बंध हैं। यह ओ.सी.सी.आर.पी. एम्स्टर्डम न्यूज़ नैटवर्क है। मीडिया पार्ट ने कहा कि ओ.सी.सी.आर.पी. जो खुद को विश्व का सबसे बड़ा खोजी पत्रकार संगठन मानता है, आर्थिक रुप से अमेरिका पर निर्भर है, इसे सोरॉस के ओपन फाउण्डेशन और यूरोपियन देशों जैसे फ्रांस व स्वीडन से भी पैसा मिलता है।

■ **कांग्रेस पार्टी ने इस घिनौने आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तथा सांसद शशि थरुर, के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, संसद की सभी परम्पराएं तोड़ी गईं, इस घिनौने आरोप से तथा इन लोगों ने संसद में पीठासीन अध्यक्ष, को लिखित में शिकायत की, तथा सभी भाजपा नेताओं द्वारा काम में लिये गये अपमानजनक शब्दों को सदन की कार्यकारी से निकालने का मांग की, जो गुरुवार को रात तक पूरी नहीं की गई।**

भाजपा ने कहा कि यह संगठन भारत विरोधी खबरे प्रकाशित करता जिनका इस्तेमाल करके कांग्रेस सत्तारुढ़ पार्टी व भारत के व्यवसायिक हितों पर निशाना साधती है। उन्होंने कहा इसी संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने को वैक्सीन पर निशाना साधा था।

पैगसस पर भी इसी संस्थान ने रिपोर्टिंग की थी जिसके आधार पर विपक्ष ने सरकार पर विरोधियों की जासूसी करने का आरोप लगाया था।

भाजपा सांसद सम्बित पात्रा ने गुरुवार सुबह प्रैस कॉन्फ्रैंस बुलाकर दावा किया इसमें जॉर्ज सोरॉस और अमेरिका की एजेंसियां और ओ.सी.सी.आर.पी. शामिल है।

भारत के जॉर्ज सोरॉस विवाहित व्यक्ति है। दक्षिणपंथी आरोप लगाते है कि वह भारत विरोधी तत्वों को मदद करता है तथा पश्चिम को एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए दुनियाभर में तख्तापलट को उकसाता है।

पात्रा ने कहा यह एक त्रिकोण है एक कोने पर जॉर्ज सोरॉस व अमेरिकन संस्थाएं है और दूसरे पर ओ.सी.सी.आर.पी. और सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा कोना है राहुल गांधी ''उच्च दर्जे का गद्दार''। मुझे यह शब्द कहने में कोई डर नहीं है। विपक्ष के नेता को गद्दार कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। पात्रा ने गांधी पर भारत से विश्वासघात करने के आरोप लगाया और कहा वे ओ.सी.सी.आर.पी. के निर्देशों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा ओ.सी.सी.आर.पी. ग्लोबल मीडिया एजेंसी है और ओपन सोसायटी फाउण्डेशन बड़ी दानदाता। यह संस्था जॉर्ज सोरॉस की है। इस आरोप को भाजपा के निशिकांत दुबे ने संसद में दोहराया और आरोप लगाया कि प्र.मंत्री मोदी से नफरत करने के कारण भाजपा सरकार गिराना चाहती है।

दुबे ने कहा जॉर्ज सोरॉस अन्य देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट करने के षडयंत्र रचते हैं। उनकी वजह से ही 1991 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बंद हो गया था। इससे सोरॉस को 6 अरब रु. का फायदा हुआ था अब वे भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने में जुटे हैं।

दुबे के आरोप पर कांग्रेसियों ने जोरदार विरोध जताया भारी हल्ला गुल्ला हुआ भाजपा सांसदों ने दुबे के पक्ष में मेजे थपथपाई। विपक्ष ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिकन सीनेटर इल्हान ओमर से मिले थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए ओमर मोदी के आलोचक हैं।

उन्होंने कहा कांग्रेस जवाब दे इन मुलाकातों में क्या साजिश रची गई क्योंकि वे राहुल गांधी के विदेशी दौरों में भारत विरोधी एजेंडा पर काम करते हैं। कांग्रेस ने इस प्रकरण को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा मानवीय स्पीकर ने दुबे को शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी इस बार विपक्ष के नेता व वायनाड सांसद व समूची कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ जो नितांत अस्वीकार्य है। शशि थरुर ने भी दुबे पर निशाना साधा व कहा, अव्वल तो आप लोगों पर इस मर्यादाहीन तरीके से हमला नहीं कर सकते हैं, दूसरे सम्बधित व्यक्ति को नोटिस दिए बिना उसका नाम नहीं ले सकते हैं।

तीसरे, आप संसदीय विशेषाधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। थरुर ने पत्रकारों को कहा कि उन्होंने सभी नियम तोड़े हैं, हमने स्पीकर से मांग की है कि उनकी टिप्पणी सदन की कार्यवाही से हटाई जाए उनसे माफी मांगने को कहा जाए। पर ऐसा अभी तक भी नहीं हुआ है।

जस्टिस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के वकील के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जनवरी 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें वरिष्ठ एडवोकेट का दर्जा दे दिया था और 13 मार्च, 2008 को वे दिल्ली उच्च न्यायालय के ऐडिशनल जज बने तथा 17 दिसम्बर, 2009 को वे इस पद पर स्थाई कर दिये गये थे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908